



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक 1937 (श०)

(सं० पटना 1253) पटना, शुक्रवार, 6 नवम्बर 2015

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

28 अप्रैल 2015

सं० 8/आ० (राज०नि०)-१-०४/२०१३-१९११—श्री विद्यानन्द पासवान, तत्कालीन निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त उप निबंधन महानिरीक्षक के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली १९५० के नियम ४३बी० के तहत महालेखाकार लेखा परीक्षक बिहार, पटना द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला अवर निबंधन कार्यालय कैमूर (भमुआ) वर्ष २००८ से २०११ तक एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय भेजपुर के वर्ष २००६ से २०११ तक के संदर्भित विलेखों के निष्पादन के क्रम में राजस्व की क्षति, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही तथा शिथिलता बरतने आदि के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या—४५०९ दिनांक १६.१०.२०१४ द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने गै०स०प्र०० संख्या—२० दिनांक १३.०१.२०१५ द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री पासवान पर कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने का आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है।

3. विभागीय पत्रांक—७६८ दिनांक १९.०२.२०१५ द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली २००५ यथा संशोधित २००७ के नियम १८ (३) के अंतर्गत द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई।

4. श्री पासवान द्वारा दिये गये बचाव बयान की समीक्षा की गई और पाया गया कि उन्होंने अपने द्वितीय बचाव बयान में इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि संभव है कुछ मामलों में आदेश फलक में स्थल जाँच का

उल्लेख भूलवश अंकित नहीं किया जा सका हो। इस आधार पर उनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया और निष्कर्षित किया गया है कि अवर निबंधन कार्यालय, कैमूर एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय, भोजपुर (आरा) द्वारा रेफर किये गये 47A के अधीन मामलों में बिना कोई जाँच किये एवं बिना कोई ठोस आधार के आदेश पारित कर राजस्व क्षति पहुँचाई गई है।

5. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा समरूप मामले में अपने पत्रांक-2508 दिनांक 22.01.2015 द्वारा परामर्श दिया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन की कटौती के विनिश्चत दण्ड प्रस्ताव में आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

6. अतएव पूर्ण विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 139 (C) में निहित प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पासवान के पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) की कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1253-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>